



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (प्रस्ताधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, गंगलवार, 5 अप्रैल, 1994/15 चैत्र, 1916

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 5 अप्रैल, 1994

सं० 1-28/94-वि०स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत "उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 1994

(1994 का विधेयक संख्यांक 9)" जो आज दिनांक 5 अप्रैल, 1994 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो गया है, सर्वसाधारण की सूचनाएं राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

लक्ष्मण सिंह,  
सचिव।

1994 का विधेयक संख्यांक 9.

## उप-मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 1994

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

उप-मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 5)  
का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा  
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उप-मंत्रियों के वेतन और भत्ता संक्षिप्त नाम  
(हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 1994 है। और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. उप-मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (जिसे धारा 3 का  
इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में "एक हजार चार सौ" संशोधन।  
शब्दों के स्थान पर "एक हजार पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे।

3. मूल अधिनियम की धारा 3-क में "छः सौ" शब्दों के स्थान पर "नौ सौ" धारा 3-क  
शब्द रखे जाएंगे। का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 6-क में "बीस हजार" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां धारा 6-क  
वे आते हैं, "चालीस हजार" शब्द रखे जाएंगे। का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) में प्रथम परन्तुक में धारा 9 का  
"आठ सौ" शब्दों के स्थान पर "एक हजार पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे। संशोधन।

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय में तेज वृद्धि और खर्चों के कारण जोकि राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को जन-प्रतिनिधियों के रूप में जनजीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, उनकी विद्यमान उपलब्धियों और सुख-सुविधाओं पर पुनर्विचार करने की निरन्तर मांग रही है। इस विषय से निपटने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को माननीय सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों के समय-समय पर उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं और सुख-सुविधाओं के बारे में सुझाव देने के लिए विधान सभा के नौ सदस्यों से मिल कर बनी "सदस्य सुख-सुविधा समिति" गठित की गई थी। भत्तों और अन्य सुख-सुविधाओं में वृद्धि करने की सिफारिश से युक्त उक्त समिति की रिपोर्ट 25-3-1994 को विधान सभा के पटल पर रखी गई थी उपर्युक्त सिफारिशों के अनुसरण में, विधायकों के भत्तों और सुख-सुविधाओं से सम्बन्धित अधिनियमिता का संशोधन किया जा रहा है। अतः उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 में उचित संशोधन करके उप-मन्त्रियों को उपलब्ध वेतन और भत्तों/सुख-सुविधाओं में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

वीरभद्र सिंह,  
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

5 अप्रैल, 1994.

### वित्तीय जापन

विधेयक के खण्ड 2 से 5 में अन्तर्विष्ट उपवन्धों के अभिनियमित होने पर राज्य की संचित निधि से अतिरिक्त आवर्ती खर्च अन्तर्वलित होगा। वर्तमानतः उप-मन्त्री का कोई पद नहीं है, अतः अन्तर्वलित वार्षिक खर्च का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है।

### प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी जापन

—शून्य—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[नस्ति सं० जी० ए० डी० (पी० ए०) 4-23/94-]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उप-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 1994, की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

## AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 9 of 1994.

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF DEPUTY MINISTERS  
(HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT BILL, 1994

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

## BILL

*further to amend the Salaries and Allowances of Deputy Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 (Act No. 5 of 1971).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title  
and com-  
mencement.

1. (1) This Act may be called the Salaries and Allowances of Deputy Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 1994.

(2) It shall come into force at once.

Amendment  
of section  
3.

2. In section 3 of the Salaries and Allowances of Deputy Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 (hereinafter referred to as the principal Act), for the words "one thousand and four hundred", the words "one thousand and five hundred" shall be substituted.

5 of 1971

Amendment  
of section  
3 A.

3. In section 3A of the principal Act, for the words "six hundred", the words "nine hundred" shall be substituted.

Amendment  
of section  
6 A.

4. In section 6A of principal Act, for the words "twenty thousand" wherever they occur, the words "forty thousand" shall be substituted.

Amendment  
of section  
9.

5. In section 9 of the principal Act, in sub-section (1), in first proviso, for the words "eight hundred", the words "one thousand and five hundred" shall be substituted.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expense which the Hon'ble Members of the State Legislative Assembly, as public representatives, had to incur on account of various demands of public life, there had been persistent demand for reconsideration of their existing emoluments and amenities. In order to sort out the matter a nine member Committee *i. e.* "Members Amenities Committee" consisting of MLAs was set up *inter alia* to suggest to the Government the facilities and amenities to be provided to the Hon'ble Members and *ex-Members* from time to time. The Report containing the recommendations of the said Committee to increase the allowances and other amenities was laid on the Table of the House on 25-3-1994. In pursuance of the aforesaid recommendations, the enactment concerning the allowances and amenities of MLAs is being amended. It has, therefore, also become necessary to increase the salary and allowances/amenities available to the Deputy Ministers by making suitable amendments in the Salaries and Allowances of Deputy Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 1971.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

VIRBHADRA SINGH,  
Chief Minister.

SHIMLA:

The 5th April, 1994.

## FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions contained in clauses 2 to 5 of the Bill, when enacted, will involve extra recurring expenditure from the Consolidated Fund of the State. At present there is no office of Deputy Minister, as such the annual expenditure involved cannot be anticipated.

---

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

NIL

---

## RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[FILE No. GAD (C) (PA) 4-23/94]

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Salaries and Allowances of Deputy Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Bill, 1994, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.